भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2083
उत्तर दिनांक 06/08/2026 को दिया गया

परमाणु क्षमता का विस्तार

2083. श्री राघव चड्ढा

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान परमाणु ऊर्जा सृजन क्षमता के विस्तार की दिशा में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान संस्वीकृत, निर्माणाधीन तथा चालू किए गए परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त वर्षों के दौरान क्षमता विस्तार हेतु कितनी धनराशि आवंटित तथा उपयोग की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखानुसार नाभिकीय ऊर्जा मिशन (एनईएम) की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है ताकि भारत के ऊर्जा मिश्रण में विश्वसनीय मूल भार ऊर्जा के रूप में नाभिकीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सके। सरकार ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की व्यापक भागीदारी को सक्षम करने के लिए शांति अधिनियम भी लागू किया है। इसके अलावा, सरकार ने एसएमआर और नई उन्नत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास को सक्षम करने के लिए उपायों की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, एनपीसीआईएल कठिनाई से कार्बन मुक्ति वाले क्षेत्रों के विकार्बनीकरण हेतु भारत लघु रिएक्टरों (बीएसआर) की स्थापना में इच्छुक कम्पनियों के साथ भी संलग्न है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान, 10100 मेगावाट की क्षमता वाले तेरह रिएक्टर निर्माण/कमीशनन के विभिन्न चरणों में थे। इनमें से 2100 मेगावाट की कुल क्षमता वाले तीन रिएक्टरों ने वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया है:

राज्य	स्थान	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)
गुजरात	काकरापार	केएपीपी-3 व 4	2 X 700
राजस्थान	रावतभाटा	आरएपीपी-7	1 X 700

8000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले शेष दस रिएक्टर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं:

राज्य	स्थान	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)
राजस्थान	रावतभाटा	आरएपीपी-8	1 X 700
तमिलनाडु	कुडनकुलम	केकेएनपीपी-3 व 4	2 X 1000
		केकेएनपीपी-5 व 6	2 X 1000
कर्नाटक	कैगा	कैगा-5 व 6	2 X 700
हरियाणा	गोरखपुर	जीएचएवीपी-1 व 2	2 X 700
तमिलनाडु	कल्पाक्कम	पीएफबीआर	1 X 500

(ग) एनपीसीआईएल: पिछले पांच वित्तीय वर्षों में नाभिकीय विद्युत क्षमता के विस्तार के लिए निर्माण/ कमीशनन अधीन, चालू और नई परियोजनाओं के लिए ₹81287 करोड़ आवंटित किए गए जिसमें से ₹81188 करोड़ का उपयोग कर लिया गया है।

भाविनि: पिछले पांच वित्तीय वर्षों में, बजट आकलन चरण में पीएफबीआर के निर्माण/कमीशनन के लिए ₹2580 करोड़ आवंटित किए गए जिसमें से ₹1600 करोड़ का उपयोग कर लिया गया है।

*****